हरियाणा का बिजली संकट
मुख्यमंत्री के दावे थोथे

चंडीगढ़ (म.मो.) बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करने वाले और हर क्षेत्र में हरियाणा को नं. 1 घोषित करने वाले मुख्यमंत्री हुड्डा यह साफ़-साफ़ कह रहे हैं कि तीन वर्ष से कम समय में बिजली संकट दूर नहीं होने वाला है। इसके वे अनेकानेक कारण बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के पूर्व सभी सरकारों ने दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीद कर काम चलाया है।

अपने शासन के पहले दौर में हुड्डा ने भी यही किया था। सच्चाई इन्हें मालुम थी। फिर भी राज्य में बिजली की उपलब्धता का इन्होंने खूब ढोल पीटा। पर अभी जुम्मा-जुम्मा आठ रोज शासन संभाले हुए नहीं कि लगे बिजली का रोना रोने। जनता को इस बात से क्या लेना-देना कि कहां का पावर प्लांट कब चालू होगा, कौन प्लांट किस स्थिति में है आदि-आदि।

जनता को तो महज़ मतलब इस बात से है कि उसे बिजली मिले चाहे, जहां से मिले। वैसे जनता इतना जरूर जानती है कि बिजली हुड्डा के घर से नहीं आती। फिर भी जहां से बिजली आती है, वह समुचित रूप से आए ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। अब बिजली उपलब्ध कराने का काम मुख्यमंत्री हुड्डा एवं उनके सहयोगियों का है।

ये नं. 1 हरियाणा की माला जपते रहे हैं और अभी जपेंगे। पर जब बिजली नहीं रहेगी तो कहां से नं. 1 हरियाणा? उद्योग हों या कृषि, सभी बिजली पर आधारित हैं। बिजली की कमी से स्वाभाविक है फैक्ट्री उत्पादन और अनाज उत्पादन पर असर पड़ेगा। क्या सिर्फ 'नं. 1 हरियाणा' का मंत्र जाप करने से बिजली चली आएगी। पिछले शासन के दौरान हुड्डा ने उद्घाटन-शिलान्यास आदि खूब कर लिए। अब उसका परिणाम सामने आना चाहिए था। अब हुड्डा बिजली की समुचित व्यवस्था करने के लिए तीन साल का समय मांगते हैं। पूछना चाहिए कि जो काम गत पांच साल में नहीं हो सका, वह तीन साल में कैसे हो जाएगा? क्या तीन साल में सरकार के पास कोई जादू की छड़ी आ जाएगी?

> "दरअसल, तीन साल में मुख्यमंत्री हुड्डा और इनके सहयोगी जमकर लूटपाट मचाएंगे और तब तक फिर चुनाव का गहमागहमी वाला समय आ जाएगा। राजनीतिक परिदृश्य में सिर्फ चुनाव-चुनाव ही हावी रहेगा। उस समय तक के लिए हुड्डा और उनके सहयोगी विकास के लिए कुछ नए नारे गढ़ लेंगे और उसी के माध्यम से जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे। रहा सवाल जनता का तो वह चुप न बैठे। वह सीधा मुख्यमंत्री से सवाल पूछे कि चुनाव प्रचार करते वक्त वे यह क्यों नहीं कहते थे कि जीतने पर तीन साल के बाद बिजली लाऊंगा। ऐसा कहते तो जनता तुरंत उनका हिसाब-किताब कर देती। अब जनता को इस सवाल पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और सीधा सवाल पूछना चाहिए कि तीन साल किसने देखा है, बिजली लानी हो तो अभी लाओ, वरना लिखकर दो कि राज्य को बिजली सुविधा मुहैया नहीं करा सकता।"

दरअसल, तीन साल में मुख्यमंत्री हुड्डा और इनके सहयोगी जमकर लूटपाट मचाएंगे और तब तक फिर चुनाव का गहमागहमी वाला समय आ जाएगा। राजनीतिक परिदृश्य में सिर्फ चुनाव-चुनाव ही हावी रहेगा।

उस समय तक के लिए हुड्डा और उनके सहयोगी विकास के लिए कुछ नए नारे गढ़ लेंगे और उसी के माध्यम से जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे।

रहा सवाल जनता का तो वह चुप न बैठे। वह सीधी मुख्यमंत्री से सवाल पूछे कि चुनाव प्रचार करते वक्त वे यह क्यों नहीं कहते थे कि जीतने पर तीन साल के बाद बिजली लाऊंगा।

ऐसा कहते तो जनता तुरंत उनका हिसाब-किताब कर देती। अब जनता को इस सवाल पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और सीधा सवाल पूछना चाहिए कि तीन साल किसने देखा है, बिजली लानी हो तो अभी लाओ, वरना लिखकर दो कि राज्य को बिजली सुविधा मुहैया नहीं करा सकता। सच पूछा जाए तो दूसरे नेताओं की भांति ही हुड्डा को झूठ बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आती। जनता इस बात को जानती है कि विकास का पहिया बिजली पर आधारित है और जब बिजली नहीं होगी तो वह चलेगा कैसे?

शिक्षा विभाग में हो रहा भद्दा मजाक
चुनाव आचार संहिता के बाद अब फ़ाइल सीएम सेल में

फरीदाबाद (म.मो.) शहर के दो सरकारी महाविद्यालयों में दसियों प्राध्यापकों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। इनमें से विज्ञान तथा गणित की अनेकों पोस्टें खाली पड़ी हैं। जबकि कुछ पोस्टें अतिथि प्राध्यापकों से भर कर काम चलाने का दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि इन अतिथि को मात्र 12000मासिक देकर सरकार 50000 रुपये के प्राध्यापकों वाला काम लेना चाहती है; जाहिर है ऐसे में केवल वही लोग अतिथि अध्यापन करेंगे जिन्हें कोई और ढंग का काम न मिले। कहने की जरूरत नहीं इस दौरान उनका ध्यान अध्यापन की बजाए कोई और बेहतर काम ढूंढने में लगना स्वाभाविक ही है। इतना ही नहीं इन अतिथि अध्यापकों को मार्च 2009 के बाद से अब तक वेतन भी नहीं मिला है।

गत वर्ष नियुक्त अतिथि अध्यापकों के बावजूद चालू शिक्षा सत्र में राज्य भर में सैंकड़ों प्राध्यापकों की कमी है। विदित है कि जुलाई माह में नया शिक्षा सत्र चालू होता है। जुलाई माह में ही कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके आधार पर ही फ़ैसला लिया जाता है कि किस विषय अथवा विभाग में कितने अतिथि अध्यापकों की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह निर्णय पूरे अगस्त व सितंबर माह में भी नहीं लिया जा सका, क्योंकि इस काम में न तो किसी अफ़सर की कोई रुचि थी और राजनेताओं की तो होनी ही क्या थी, क्योंकि उन्हें तो चुनाव दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान चुनाव आचार संहिता लग गई। इस दौरान तो कोई कामकाज करने की जरूरत ही नहीं और शिक्षा जैसे विभाग में तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं समझी जाती। जिन तबादलों एवं नियुक्तियों को सरकार ने आवश्यक समझा था, उन्हें तो उसने आचार संहिता से पहले कर ही कर लिया था।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सरकार बनने की प्रक्रिया रूपी नाटक राज्य की जनता देखती रही। जरूरतमंद छात्र, नये अथिति अध्यापकों की और पुराने अथिति अध्यापक अपने रु हुए वेतन की बाट जोहते रहे। सरकार बनने का नाटक पूरा हो जाने के बाद जब बातचीत चलाई गई तो चंडीगढ़ से जवाब मिला कि 'फ़ाइल सीएम सेल' में गई है। दुर्भाग्य इस देश का कि कोई पूछने वाला नहीं इस सरकार व इसके अफ़सरों को कि शिक्षा सत्र का आधा निकल चुका है और फ़ाइल अभी सीएम सेल में अंडे दे रही है और दो-तीन महीने ऐसे ही अंडे देती रहे तो फ़िर उसकी सेल से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या रह जायेगी?

यह समस्या कोई एक फरीदाबाद के मात्र दो कॉलेजों की नहीं है, बल्कि राज्य भर के 88 कॉलेजों की है जो सरकारी लालफीताशाही के नीचे दबे हैं। इन सभी सरकारी कॉलेजों में 1575 प्राध्यापकों की कमी है जिनमें से कुछ तो अथिति प्राध्यापक लगा दिये हैं बाकी रामभरोसे चल रहा है। इस समस्या से निपटने के लिये राज्य की 'सूझवान' सरकार के अति 'विद्वान' अफ़सरों ने जो फ़ार्मूला निकाला वह भी गजब का है। इसके मुताबिक यदि झज्जर में गणित का एक भी प्राध्यापक नहीं है तो एक प्राध्यापक को तीन माह की अस्थाई नियुक्ति पर फरीदाबाद से भेज दिया जाये जहां पहले से ही बेशक चार की जगह दो ही प्राध्यापकों से काम चलाया जा रहा हो।

पृष्ठ 3 का शेष

पहला पुल : सुग्रीव यह सुन कर चौंक पड़ा। कहने लगा, 'महाराज, आप कैसी अनहोनी बात करते हैं? सेना कैसे कूच कर सकती है? अभी पुल का उद्घाटन तो हुआ नहीं है।' राम समझाने लगे, 'देखो बंधु, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक मिनट की देर होने से भी सीता का अहित हो सकता है। हमें उद्घाटन की प्रथा को पालना इस समय आवश्यक नहीं है।' सुग्रीव तो आसमान से गिरते-गिरते बचा। बोला, 'ऐसा भी कहीं होता है। बिना विधिवत उद्घाटन के पुल पर एक क़दम नहीं रखा जा सकता। कितने पुल वर्षों से बन कर पड़े हैं, पर उन पर कोई नहीं चलता क्योंकि उनका उद्घाटन नहीं हो सका है। महाराज, पुल पार उतारने के लिए नहीं, बल्कि उद्घाटन के लिए बनाये जाते हैं। पार उतरने के लिए उनका प्रयोग हो जाता है, यह प्रासंगिक बात है।

सुग्रीव की हठ देख कर राम कुछ झुके। बोले, तो फ़िर जल्दी करो। किससे उद्घाटन कराया जाए? सुग्रीव ने झट कहा, 'मेरी अल्प मति के अनुसार आपके श्वसुर जनक जी के कर-कमलों से पुल का उद्घाटन होना चाहिए।'

राम ने सहमति प्रकट की, ठीक है। इसी क्षण निमंत्रण भेजो।

राजा जनक अपने दल समेत मिथिला से चले और कुछ दिनों में सागर तट पर आ गये। उनकी यात्रा का खर्च सुग्रीव ने ही दिया और उसने हिसाब लगाया कि जितना जनक के आने में खर्च हुआ, उतने से दो पुल और बन सकते थे।

उद्घाटन के लिए एक मुहूर्त निश्चित किया गया। जनक ने पूजा की और सोने की कैंची से फीते को काटा।

वानरों ने जयनाद किया, 'राजा जनक की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा सुग्रीव की जय'

जनक ने इसके बाद वानरों की सभा में भाषण दिया, 'भाइयो, रामचंद्र ने मुझे इस पुल का उद्घाटन करने के लिए बुला कर मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने मुझे बुला कर उचित ही किया क्योंकि वे मेरे दामाद हैं। वे और किसे बुलाते? भाइयो, राष्ट्र के जीवन में पुलों का जो महत्त्व है, यह किसी से छुपा नहीं है। आज अपने देश का हमें निर्माण करना है और निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास बड़ी संख्या में पुल न हों। पुल ही राष्ट्र की पूंजी हैं और पुलों के बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। संसार का इतिहास उठा कर देखो-वही राष्ट्र प्रगति कर सका जिसके पास काफ़ी पुल थे। इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश में पुल ही पुल बनें। नदियों पर पुल बनें। सागरों पर पुल बनें, महासागरों पर पुल बनें। यही नहीं हवा में पुल बनें, जैसे हवा में महल बनते हैं। इस महान पुल-निर्माण योजना की श्रृंखला में यह पुल पहली कड़ी है। मैं आपलोगों को पुन: धन्यवाद देता हूं।'

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजा जनक अपने आसन पर बैठ गये।

वे बैठे ही थे कि देखते-देखते ही वह पुल भरभरा कर गिर गया।

सुना है, उस पुल के संबंध में जो जांच कमीशन बिठाया था, उसकी रिपोर्ट कलियुग के इस चौथे चरण तक तैयार नहीं हुई। □□

आवारा कुत्तों की समस्या से परेशान शहरवासी

फरीदाबाद (म.मो.) शहर में आवारा कुत्ते लोगों की परेशानी का बहुत बड़ा सबब बन गए हैं। गत वर्ष निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें बाड़ों में रखने का वादा किया था, पर वास्तव में उसने इस संबंध में कुछ किया नहीं। साल-दर-साल आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि होती जाती है और इससे जनता की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। वैसे नगर निगम ने यह दावा किया है कि उसने बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को पकड़ा है, पर यदि पकड़ा है तो फिर ये कुत्ते अपने बाल-बच्चों के साथ सड़कों पर कैसे नज़र आ रहे हैं? आवारा कुत्ते सिर्फ सड़कों पर ही नज़र नहीं आते, बल्कि घरों में भी घुस जाते हैं और रसोई घर यदि खुला हो और वहां कोई नहीं हो तो चुपचाप माल भी चट कर जाते हैं। इसके बाद खाली बिस्तर पर आराम भी फ़रमाने लगते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा इन्हें भगाना चाहे तो भागने की जगह उस पर गुर्रा कर उसे डराने लगते हैं। बड़े आदमी के आने पर भी बड़ी ढिठाई दिखाते हुए ये भागते हैं।

इन आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले जब कुत्ते पकड़े जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। इसे लेकर पशु अधिकार का शोर मचा कर खाने-पीने वाले संगठनों ने काफी शोर-शराबा मचाया और तब तय हुआ कि आवारा कुत्तों को मारा नहीं जाएगा। इसके अलावा मृत भेड़ से कुत्ता काटने के इलाज में आने वाली जो दवा बनती थी, वह बंद हो गई, दूसरे साल दर साल कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोगों की परेशानी तो बढ़ी ही, कुत्ते के काटे मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ, सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटे मरीजों के उसके टीके दिए जाने बंद हो गए। ऐसी हालत में लोगों को इलाज के लिए बड़े प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं जहां एक गरीब आदमी की पूरी की पूरी दिहाड़ी खर्च हो जाती है। इलाज के लिए दिहाड़ी तोड़नी भी पड़ती है अलग। उल्लेखनीय है कि कुत्ते भी गरीबों को ही काटते हैं।

> "अमीरों के बच्चे तो पूरी सुरक्षा में रहते हैं और अपने पालतू विदेशी कुत्तों के साथ खेलते रहते हैं। वे गलियों में नहीं खेलते। गलियों में खेलते हैं गरीबों के बच्चे जो कुत्ता काटने के शिकार होते हैं। क्या नगर निगम इस समस्या पर ध्यान देगा? जानकार सूत्रों के अनुसार उसके पास कुत्ता पकड़ने की गाड़ी भी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, नगर निगम के एक पूर्व आयुक्त ने आवारा कुत्तों के लिए बाड़बंदी करने की बात की थी। साथ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी करने की भी योजना थी।"

अमीरों के बच्चे तो पूरी सुरक्षा में रहते हैं और अपने पालतू विदेशी कुत्तों के साथ खेलते रहते हैं। वे गलियों में नहीं खेलते। गलियों में खेलते हैं गरीबों के बच्चे जो कुत्ता काटने के शिकार होते हैं। क्या नगर निगम इस समस्या पर ध्यान देगा? जानकार सूत्रों के अनुसार उसके पास कुत्ता पकड़ने की गाड़ी भी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, नगर निगम के एक पूर्व आयुक्त ने आवारा कुत्तों के लिए बाड़बंदी करने की बात की थी। साथ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी करने की भी योजना थी। पर क्या यह सब जनता को बरगलाने के लिए थी? आवारा कुत्तों की समस्या उपेक्षित करने वाली समस्या नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे जनता त्रस्त है, वह कहे क्या और किससे कहे? छोटे बच्चों के अलावा औरतें और बुजुर्ग भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। विकराल समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब कुत्तों के दो झुंड आपस में उलझ पड़ते हैं। उस समय वे एक-दूसरे को लहू-लुहान करके छोड़ते हैं और उनके बीच दैवयोग से कहीं कोई आदमी पड़ गया तो उसका हाल पूछें ही मत।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06